

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 104/019

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:—प्रार्थी

बनाम

- 1 लक्ष्मीनारायणसिंह पुत्र मांग्या
- 2 चेताराम पुत्र मांग्या
- 3 केशव पुत्र मांग्या
- 4 शंकुन्तला पुत्री मांग्या
- 5 सरस्वती पुत्री मांग्या

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान अनन्तपुरा
तहसील टोडाभीम जिला करौली

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 07.08.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 430,431,439/998 रकवा 0.75 है0.ग्राम अनन्तपुरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 226 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन तलाई के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2039 से 42 यह भूमि मांग्या पुत्र पीरू गुर्जर अप्रार्थी के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 226 का नवीन खसरा नम्बर 430,431,439/998 रकवा 0.75 है0.बनाकर हाल जमाबंदी मे सो अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2039 से 42, 2071 से 74, मिलान क्षेत्रफल, हाल जमाबंदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

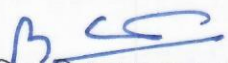
प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं. 1 ता 5 जरिये बकालान्तन उपस्थित आया ओर जबाब पेश किया अपने जवाब कथन में कहा की विवादित आराजी हमारे पिता माग्या के नाम खातेदारी थी जो नामान्तकरण संख्या 239 दिनांक 19.06.1983 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसकी किस्म बदल कर नियमन के आधार पर खातेदारी दर्ज हुई है। मौके पर कोई तलाई नही है नोटिस गलत दिया गया है। खारिज फरमाई

वकील अप्रार्थीयान की बहस सुनी। दोराने बहस अपने कथन जवाब को दोहराते हुए कहा है कि विवादित भूमि पुश्तेनि है मौके पर कोई तलाई नही है काफी वर्षो से भूमि पर कब्जा होने पर हमारे पिता माग्या को नियमन हुई है इस भूमि पर अब्दुर रहमान बनाम सरकार के निर्देश लागू नही होते है। प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थीयान की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाब एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2039 से 2042 की खाता संख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 226 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा भूमि गैरमुमकिन तलाई के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे नामान्तकरण संख्या 239 दिनांक 19.06.1983 से भूमि आवंटन हुई। ओर बाद में खातेदारी स्वीकृत हुयी थी हाल जमाबंदी सम्बत 2071 से 74 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि **All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly.** माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 430,431,439/998 रकवा 0.75 है0 ग्राम अनन्तपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2039 से 2042 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन तलाई दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।


अति० जिला कलक्टर
करौली